भारत के साथ समझौता संभव : ट्रम्प

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के करीब

अमेरिका पहली अगस्त से नए शुल्क लागू करेगा

> राष्ट्रपति ने अमेरिका से व्यापार करने वाले देशों पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अप्रैल में उनके खिलाफ ऊंचे प्रशुल्क लगा दिए है. उन्होंने इन देशों को समझौता करने के लिए 90 दिन का समय दिया था जो 9 जुलाई को पूरा हो गया है. भारत के साथ बातचीत संभावत- जारी है. उन्होंने उसके बाद कई देशों के खिलाफ ऊंचे शुल्क लगाए हैं जो पहली अगस्त से प्रभावी होने जा रहे हैं.

वाशिंगटन, 17 जुलाई (वार्ता) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर कहा है कि उनकी सरकार भारत के साथ समझौते के 'संभवत-' बहुत करीब है, क्योंकि बातचीत चल रही है.

भारत के साथ व्यापार समझौते पर यह बयान उस समय आया जब भारतीय समयानुसार बुधवार रात राष्ट्रपति ट्रम्प अपने ओवल ऑफिस में बहरीन के युवराज सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ बैठक के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने ज़ोर दिया कि पहली अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जब उनके देश में बहुत सारी धन-राशि (आयात शुल्क की कमाई) आएगी.

ट्रम्प ने कहा, हम 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा लाए हैं. ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर, प्रशुल्क में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है. पहली अगस्त वह दिन है जब हमारे देश में काफ़ी घन आ रहा होगा. हमने कई जगहों के साथ समझौते किए हैं. कल भी एक समझौता हुआ. ट्रम्प ने कहा, हमारा एक और समझौता होने वाला है, शायद भारत के साथ, हम बातचीत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, जब मैं पत्र भेजता हूँ, तो वह एक समझौता होता है. सबसे अच्छा समझौता जो हम कर सकते हैं, वह है एक पत्र का भेजना, और उस पत्र में लिखा होता है कि आप 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 20 प्रतिशत का भुगतान करेंगे. हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ अच्छे समझौते अभी बाकी हैं. हम भारत के साथ एक समझौते के बहुत करीब हैं जहाँ वे इसे (व्यापार को) खोलेंगे.

इससे पहले ट्रम्प ने इंडोनेशिया के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत ट्रंप ने उस पर पहले लागू 32 प्रतिशत प्रशुल्क की दर को घटाकर केवल 19 प्रतिशत कर दिया है. राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे सभी के लिए एक बड़ा समझौता बताया, क्योंकि इंडोनेशिया को अमेरिकी निर्यात पर कोई प्रशुल्क नहीं लगेगा, जबकि इंडोनेशिया के माल पर अमेरिका में 19 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा.

टाटा पंच ने छह लाख इकाई के उत्पादन का आंकड़ा पार किया

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (वार्ता) टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट एसयूवी 'पंच' ने चार साल से भी कम समय में छह लाख इकाई के उत?पादन का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है.

कंपनी ने गुरुवार को इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए बताया कि इस रिकॉर्ड ने पंच को देश की सबसे पसंदीदा एसयूवी के रूप में और भी मजबूत स्थान दिलाया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अकेले इसके कुल उत्पादन में 13 प्रतिशत का योगदान देता है. टाटा पंच को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था. इसने एक नये वाहन श्रेणी - सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी - की शुरुआत की. वर्ष 2024 में यह देश की सबसे अधिक बिकने वाली कार रही.

अंडमान में मिल सकते हैं बड़े तेल क्षेत्र

पुरी बोले - गुयाना जैसे भंडार की पूरी उम्मीद, 2025 तक बड़े लक्ष्य

ओएएलपी राउंड-10 के तहत 2 लाख वर्ग किमी में खुदाई

नई दिल्ली, 17 जुलाई.केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में शुरू हो रहे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के नए दौर में गुयाना के आकार के कई बड़े तेल क्षेत्र मिलेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने 'ऊर्जा वार्ता 2025' कार्यक्रम के दौरान कहा, हम ओएएलपी (ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी) राउंड-10 के तहत 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में अधिक हाइड्रोकार्बन की खुदाई और एक्सप्लोर करेंगे. हमारा लक्ष्य 2025 तक एक्सप्लोरेशन सेक्टर को 5 लाख वर्ग किलोमीटर और 2030 तक 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाना है. मुझे पूरा विश्वास है कि हमें गुयाना के आकार के कई क्षेत्र खासकर अंडमान सागर में मिलेंगे.

हरदीप पुरी ने कहा, हम एक्सप्लोरर्स के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता, वित्तीय प्रोत्साहन, स्थिर नियामक ढांचे, निवेश को जोखिम-मुक्त बनाने और ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं ताकि भारत को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन (ईएंडपी) के लिए अगला वैश्विक अग्रणी बनाया जा सके.

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 'ऊर्जा वार्ता 2025' में आयोजित 'मंच मंत्री का' कार्यक्रम में उनकी उत्साहवर्धक बातचीत हुई. यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुखों, पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों, ऊर्जा पेशेवरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और गतिशील नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा के हितधारकों का एक अनूठा सम्मेलन था.

उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, भारत ने ऊर्जा को लेकर तीन बड़ी चुनौतियों उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता का सफलतापूर्वक सामना किया है.

> केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें सरकार की प्राथमिकता बनी हुई हैं और जिन देशों से तेल और गैस का आयात किया जाता है, उनका दायरा भी विस्तृत हो गया है. उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया, एचईएलपी जैसे दूरदर्शी सुधारों के साथ, लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर के अब तक के 'नो ओपन' एरिया को ओपन किया जा रहा है और ऑयलफिल्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (ओआरडी) अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं. भारत नए क्षेत्रों की खोज करक घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के दौर से गुजर रहा है. इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्री, शीर्ष सरकारी अधिकारी और ऑयल एंड गैस सेक्टर के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए.

डिएजिओ की सीईओ ने तत्काल प्रभाव से कंपनी छोड़ी

न्यूयॉर्क, 17 जुलाई (वार्ता) दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी डिएजिओ ने बताया है कि उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेब्रा क्रू ने आपसी सहमति के तहत नियुक्ति के दो साल बाद ही कंपनी छोड़ दी है. दुनिया भर में शराब उद्योग में बिक्री में जारी सुस्ती के बीच यह औचक बदलाव सामने आया है. इससे डिएजिओ के ब्रांडों की बिक्री भी प्रभावित हुई है जिनमें जॉनी वाकर व्हिस्की, कैसामिगोस टकीला, गुइनेस बियर शामिल हैं. इसके अलावा कंपनी को अमेरिका में ऊंची टैरिफ दरों का भी सामना करना पड़ सकता है. लंदन स्थित कंपनी ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि क्रू तत्काल प्रभाव से कंपनी छोड़ रही हैं.

धन-धान्य योजना से बढ़ेगी कृषि उत्पादकता

शिवराज सिंह ने योजना को बताया ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री मोदी को जताया किसानों की ओर से आभार

हर राज्य के कम उत्पादक जिलों में कृषि योजनाओं का समेकन

नई दिल्ली, 17 जुलाई.केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की मंजूरी पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए किसानों की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद दिया.

चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खाद्यान्न, फल, दूध और सब्जियों का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, लेकिन राज्यों और जिलों में उत्पादकता में अभी भी काफी अंतर है. इस असमानता को दूर करने के लिए, कम उत्पादकता वाले या कम किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन वाले जिलों को चिन्हित किया जाएगा.

योजना का क्रियान्वयन और लक्ष्य - केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन चिन्हित जिलों में 11 विभागों की केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को कन्वर्जन के माध्यम से पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जाएगा. लगभग 100 जिलों को इस आधार पर चुना जाएगा, जिसमें हर राज्य का कम से कम एक जिला अवश्य शामिल होगा. योजना की तैयारी शुरू हो गई है.

> **समितियों का गठन और व्यापक दृष्टिकोण**
> नीति आयोग इस अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड बनाएगा. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर एक समिति बनेगी, जिसे ग्राम पंचायत या कलेक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे. राज्य और केंद्रीय स्तर पर भी टीमें गठित की जाएंगी, जिनकी जिम्मेदारी योजनाओं का सही कन्वर्जेंस सुनिश्चित करना होगा.

मृतकों का आधार अब होगा निष्क्रिय

गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यूआईडीएआई की पहल

नई दिल्ली, 17 जुलाई. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब ऐसे आधार नंबर बंद कर रहा है जो उन लोगों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके.

आधार नंबर एक 12 अंकों की खास पहचान होती है जो हर भारतीय नागरिक को दी जाती है. लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार नंबर बंद करना जरूरी हो जाता है ताकि कोई उसका गलत उपयोग न कर सके.इस काम को आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने 9 जून 2025 को 'माय आधार' पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना शुरू की. इस सेवा के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के मृत सदस्य की जानकारी देकर उनका आधार नंबर बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करनी होगी और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी और अन्य विवरण देने होंगे.

यह सुविधा फिलहाल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है, बाकी राज्यों में भी जल्द शुरू होने की तैयारी है. इसके अलावा, यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक (आरजीआई) से आधार नंबरों से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था.

जोहो ने पेश किया ज़िया एलएलएम

अंग्रेजी-हिंदी में स्पीच-टू-टेक्स्ट मॉडल भी लॉन्च

कम हार्डवेयर पर 75 प्रतिशत बेहतर परफॉर्मेंस

चेन्नई, 17 जुलाई.चेन्नई मुख्यालय वाली वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को व्यवसायों और उद्यमों के लिए एआई पेशकशों की एक श्रृंखला की घोषणा की.

कंपनी ने अपना स्वयं का बड़ा भाषा मॉडल, ज़िया एलएलएम लॉन्च किया, जिसे एनवीडिया के एआई-एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आंतरिक रूप से विकसित किया गया है. जोहो के उत्पादों के लिए प्रशिक्षित ज़िया एलएलएम में तीन मॉडल (1.3, 2.6, 7 बिलियन पैरामीटर) शामिल हैं, जो ओपन सोर्स मॉडलों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी हैं.जोहो के सीईओ मणि वेम्बु ने ग्राहक डेटा सुरक्षा, व्यापक क्षमताओं और मूल्य पर केंद्रित आंतरिक एआई विकास पर जोर दिया.

भारत में बदल रहा उपभोक्ता खर्च का पैटर्न

शहरी उपभोक्ता अब मूल्य को तरजीह दे रहे

ग्रामीण भारत में ब्रांड अपनाने की होड़

नई दिल्ली, 17 जुलाई.भारत में लोगों के खर्च करने का तरीका बदल रहा है, खासकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में. एमके रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, शहरी उपभोक्ता अब ब्रांड-निरपेक्ष होते जा रहे हैं और मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण उपभोक्ता तेजी से ब्रांडों को अपना रहे हैं और अधिक ब्रांड-सचेत हो रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी खपत की मात्रा धीमी हो रही है, और लोग अब पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और सुविधा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. मानसिकता में इस बदलाव से शहरी उपभोक्ता ऐसे उत्पादों को चुन रहे हैं जो बेहतर मूल्य प्रदान करते हैं, भले ही इसका मतलब लोकप्रिय ब्रांडों से दूर जाना हो. दूसरी ओर, ग्रामीण उपभोक्ता विपरीत प्रवृत्ति दिखा रहे हैं. वित्त वर्ष 25 में ग्रामीण क्षेत्रों में सूचीबद्ध ब्रांडों की वृद्धि तेज हुई है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण भारत अधिक महत्वाकांक्षी होता जा रहा है. वे ब्रांडेड उत्पादों पर अधिक खर्च करने को तैयार हैं, और उनमें ब्रांड चेतना बढ़ रही है.

समाचार विशेष

ओवैसी को क्यों नहीं मिली महाठबंधन में जगह?

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से पार पाने का रास्ता लालू यादव ने खोज निकाला है. साथ ही यह अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है कि क्यों एआईएमआईएम को महागठबंधन में एंट्री नहीं दी गई है. दरअसल, विधानसभा चुनाव को देखते हुए लालू की अगुवाई वाली आरजेडी अपने कोर वोटर मुसलमानों पर खास ध्यान दे रही है. इस समाज में उसने खासकर अति पिछड़ी मुस्लिम जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति बनाई है. राजद ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत अति पिछड़े मुस्लिम नेताओं में नेतृत्व उभारना शुरू कर दिया है.

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, आने वाले समय में संगठन की प्रांतीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या विधानसभा प्रत्याशी का चयन, माना जा रहा है कि इस बार अति पिछड़े मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाएगी. राजद की इस रणनीति के पीछे आरजेडी का राजनीतिक गणित है. अनुमान है कि बिहार में मुसलमानों में अति पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 67 प्रतिशत है. सूत्र बताते हैं कि एआईएमआईएम के अनुरोध को खारिज करने के पीछे आरजेडी का एक विशेष सर्वेक्षण आधार बना. पार्टी ने विभिन्न आधारों पर एक सर्वेक्षण किया है और पाया है कि वक्फ विधेयक के विरोध में राजद-कांग्रेस के जितना ज़ोर किसी और पार्टी ने नहीं दिखाया है. सर्वेक्षण से पता चला है कि मुस्लिम समुदाय एआईएमआईएम को वोट देकर महागठबंधन को कमज़ोर करने के पक्ष में नहीं है. वहीं, सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि जब भी हिंदू-मुस्लिम का नारा बुलंद होता है, उसका फ़ायदा विपक्ष से ज़्यादा भाजपा को होता है. इसलिए, आरजेडी या कांग्रेस एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करना चाहती. इसके अलावा भी मुस्लिम मतदाताओं का मूड भांपने के लिए आरजेडी ने कई अन्य अभ्यास भी किए हैं.

फिलहाल तो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपना दांव खेल दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह चाल कितनी कामयाब होती है और इसके जरिए उनकी पार्टी मुस्लिम वोटरों को बंटने से रोक पाती है या फिर नहीं!

यह है 'बिहार के चाणक्य' की चतुर चाल

> **वोटबैंक में हिस्सेदारी स्वीकार नहीं**
> इसी रणनीति के तहत लालू की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के महागठबंधन में अपनी पार्टी को शामिल करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है. आरजेडी ने अपने कोर वोटर मुसलमानों पर भरोसा जताया है. जानकारों का यह भी कहना है कि आरजेडी अपने कोर वोटरों में किसी की हिस्सेदारी स्वीकार नहीं करेगा. इसके लिए उसने अपने कोर मुस्लिम वोटरों में अति पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाई है. मुसलमानों में यह एक ऐसा वर्ग है, जिसके वोटों से ज्यादातर मुसलमान चुनाव जीतते रहे हैं. जबकि इस वर्ग के प्रतिनिधियों की संख्या इसमें बहुत कम है. ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संभव है कि सवर्ण जातियों के मुसलमान बहुत कम दिखें. फ़िलहाल, आरजेडी में ज्यादातर मुस्लिम नेता मुसलमानों में सवर्ण जातियों से ही ताल्लुक रखते हैं.

अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे नरेश मीणा!

जयपुर. पिछले साल उपचुनाव के दौरान टोंक की देवली-उनियारा विधानसभा सीट के समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरोपी नरेश मीणा 8 महीने बाद सोमवार को जेल से बाहर आ गए. नरेश को राजस्थान हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को ज़मानत दी थी. जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा सीधे समरावता गांव पहुंचे और वहां के लोगों से मुलाक़ात की.

राजस्थान अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है, लेकिन क्या इस साल ही नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच पाएंगे ? इसके बारे में क़यास लगाए जा रहे हैं. राजस्थान की राजनीति पर नज़र रखने वाले मान रहे हैं कि इस वक्त नरेश मीणा की लोकप्रियता उठान पर है, ऐसे में वो इसका फायदा उठाना चाहेंगे. लेकिन सवाल यह है कि कैसे ?

दरअसल बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में सजा हो चुकी है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्टेट एडवाकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर मीणा की सदस्यता को आधिकारिक रूप से रद्द घोषित कर दिया है. इस फैसले के बाद से ही एक बार फिर प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन गई है. अंता सीट को अब खाली घोषित किया गया है और जल्द ही चुनाव होने की संभावना है.

अंता सीट पर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया का दबदबा रहा है. जैन यहां से विधायक रहे हैं और पूरवर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं.

> **भाजपा के दबदबे वाली सीट**
> अंता विधानसभा सीट पर साल 2023 के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत 80.35 दर्ज किया गया था. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कंवर लाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5861 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी. अंता विधानसभा, झालावाड़-बारां लोकसभा सीट के तहत आती है. लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा का दबदबा कायम रहा. भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया को 3,70,989 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी.

बंद से बनी विपक्ष की एकजुटता

पटना. बिहार में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई दिख रही थीं. कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम अकेले हो रहे थे. इस साल के पहले छह महीने में राहुल गांधी पांच बार बिहार दौरे पर पहुंचे और हर बार उनका कार्यक्रम अकेले हुआ. उसमें राजद या कम्युनिस्ट पार्टियों को नहीं शामिल किया गया.

पहली बार एक साझा कार्यक्रम हुआ. बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सड़क पर उतरी. अब तक अलग राजनीति कर रहे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता भी राजद और कांग्रेस के साथ मंच पर आए. इतना ही नहीं विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी विपक्ष के साथ सड़क पर उतरे, जिनके बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं और कहा जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हैं. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के एक साथ खुली जीप में पटना की सड़कों पर निकलने से एक बहुत पावरफुल तस्वीर बनी है. विपक्षी पार्टियां इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रही हैं कि उसने सबको एकजुट कर दिया.

विशेष

सिद्धारमैया और डीकेएस से क्यों नहीं मिले राहुल?

बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार चार दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी उनसे नहीं मिले. ये दोनों नेता कर्नाटक से दिल्ली सिर्फ राहुल गांधी से मिलने आए थे. सरकारी कार्यक्रम भी था, जो पहले ही दिन निपट गया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात थी. उसके बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी मिलेंगे लेकिन मुलाकात नहीं हुई. इस दौरान राहुल एक दिन बिहार गए, जहां उन्होंने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ चक्का जाम में हिस्सा लिया और एक दिन भोपाल गए. इन दोनों दिन वे रात में वापस लौट आए थे. लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी.

बताया गया कि कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से सिद्धारमैया और शिवकुमार की मुलाकात हुई. यह क्या मुलाकात थी? पिछले ही हफ्ते सुरजेवाला कर्नाटक गए थे और बेंगुलूरू में सबसे मिल कर लौटे थे. फिर दिल्ली में उन्हीं से मिलने के लिए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं आए थे! जिस दिन सुरजेवाला से दोनों की मुलाकात हुई उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में थे और वहां सिद्धारमैया सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई. खबर है कि सुरजेवाला पिछले दो हफ्ते में कर्नाटक कांग्रेस के एक सौ से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं. खड़गे और सुरजेवाला की सक्रियता से जाहिर है कि कर्नाटक में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है.